

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 163]

No. 163]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 29, 2004/चैत्र 9, 1926

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 29, 2004/CHAITRA 9, 1926

पुरा विभाग

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2004

सा.का.नि. 230(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

“सं० आ० 199”

संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 2004

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात्:—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 2004 है।
2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।
3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2003 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, निचे विनिर्दिष्ट राज्यों में से प्रत्येक के लिए राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में, उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां, जो राज्यों में चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़ और ओलावृष्टि के पीड़ितों को राहत देने के लिए राज्य विपत्ति राहत निधियों के संबंध में केन्द्रीय सरकार के अभिदाय के रूप में हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होंगी:—

राज्य	रुपए लाख में
(1)	(2)
1. आन्ध्र प्रदेश	17196.00
2. अरुणाचल प्रदेश	1044.00
3. असम	4406.00
4. बिहार	2907.00
5. छत्तीसगढ़	1192.50
6. गोवा	159.50
7. गुजरात	14013.00
8. हरियाणा	7059.00
9. हिमाचल प्रदेश	3775.00
10. जम्मू-कश्मीर	3030.00
11. झारखंड	7149.00
12. कर्नाटक	6474.00
13. केरल	5838.00
14. मध्य प्रदेश	5439.00
15. महाराष्ट्र	17231.75
16. मेघालय	342.00
17. मिजोरम	252.00
18. नागालैंड	166.00
19. उड़ीसा	9504.00
20. पंजाब	10655.00
21. राजस्थान	13479.00
22. सिक्किम	885.50
23. तमिलनाडु	8911.00
24. उत्तर प्रदेश	12700.00
25. उत्तरांचल	4148.00
26. पश्चिमी बंगाल	8778.00

परन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां ऊपर विनिर्दिष्ट प्राकृतिक विपत्तियों के संबंध में राहत देने के लिए उपायों पर 1 अप्रैल, 2003 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में व्यय की जाएंगी :

परन्तु यह और कि राहत उपायों पर वास्तविक व्यय, जैसा कि इस वर्ष के लेखाओं में प्रकट किया गया है, ऊपर विनिर्दिष्ट राशियों से कम है तो, अतिशेष, राज्य की विपत्ति राहत निधि के भाग के रूप में राज्य सरकार को उपलब्ध बना रहेगा ।

(2) 1 अप्रैल, 2003 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में किसी राज्य को उप-पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 6 आदेश, 2003 के पैरा 3 के उप-पैरा (1) के अनुसरण में वित्तीय वर्ष में उस राज्य को संदेय राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी।

ए. पी. जे. अब्दुल कलाम,

राष्ट्रपति।

[फा. सं. 19(1)/2004-वि. 1]

टी. के. विश्वनाथन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2004

G.S.R. 230(E).—The following Order made by the President is published for general information:—

“C.O. 199”

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) ORDER, 2004

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 2004.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2003, as grants-in-aid of the revenues of each of the States specified below, the sums specified against it as representing the contribution of the

Central Government towards State Calamity Relief Funds for affording relief to the victims of cyclone, drought, earthquake, fire, flood and hailstorm in the States:—

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
1. Andhra Pradesh	17196.00
2. Arunachal Pradesh	1044.00
3. Assam	4406.00
4. Bihar	2907.00
5. Chhattisgarh	1192.50
6. Goa	159.50
7. Gujarat	14013.00
8. Haryana	7059.00
9. Himachal Pradesh	3775.00
10. Jammu and Kashmir	3030.00
11. Jharkhand	7149.00
12. Karnataka	6474.00
13. Kerala	5838.00
14. Madhya Pradesh	5439.00
15. Maharashtra	17231.75
16. Meghalaya	342.00
17. Mizoram	252.00
18. Nagaland	166.00
19. Orissa	9504.00
20. Punjab	10655.00
21. Rajasthan	13479.00
22. Sikkim	885.50
23. Tamil Nadu	8911.00
24. Uttar Pradesh	12700.00
25. Uttaranchal	4148.00
26. West Bengal	8778.00:

Provided that the sums specified above shall be expended in the financial year commencing on the 1st day of April, 2003 on measures for affording relief in connection with natural calamities specified above:

Provided further that if the actual expenditure on relief measures as revealed in the accounts of this year is lower than the sums specified above, the balance shall remain available to the State Government as part of the Calamity Relief Fund of the State.

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) to any State, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2003 shall be in addition to the sum or sums payable to that State in the financial year in pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Constitution (Distribution of Revenues) No. 6 Order, 2003.

A. P. J. ABDUL KALAM,
President.

[F. No. 19(1)/2004-L.I.]

T.K. VISWANATHAN, Secy.